RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-11
November-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i11.016

बिहार में सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय का उभार

डॉ. चिंटू

सहायक अध्यापक, अन्जबित सिंह कॉलेज, बिक्रमगंज (रोहतास), वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 14 November 2020

Keywords
सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग, बिहार, वामपंथी पार्टियां,राजद, सीपीआई ,माकपा, भाकपा-माले

***Corresponding Author**
Email: chintumkumari[at]gmail.com

ABSTRACT

बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ राजनीतिक शक्ति लम्बे समय तक उच्च जाति एवं वर्ग के पास रही. लेकिन मध्यम वर्ग भी राजनीतिक- आर्थिक हिस्सेदारी के लिए लम्बे समय से अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगा रहा. यहाँ की पारंपरिक सत्ता को तथा राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व को चुनौती 1970 के दशक में मिलने शुरू हुई. और 1990 के दशक में पिछड़े वर्ग की राजनीति का उभर अपने चर्म पर था जब लालू यादव ने बिहार के मुख्य मंत्री के रूप में सत्ता संभाला. सत्ता का लोकतंत्रीकरण एक झटके में नहीं हुआ बल्कि इसके लिए एक लम्बा समय लगा जिसकी जड़े स्वतंत्र से पहले से देखी जा सकती हैं

1.परिचय

लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि जब भी सत्तापक्ष खुद को संप्रभु समझने लगती है तब जनता उनकी धनबल और बहुबल के अहंकार को तोड़ने का दम ख़म रखती है. वामदलों को छोड़ दें तो बिहार की जनता ने हर रंग और विचार की पार्टियों को सत्ता सँभालने का मौका दिया. वर्तमान में 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने शिक्षा , रोजगार, और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को केंद्रीय महत्व के विषय के रूप में पहचान दी . सभी दलों और विचारों की पार्टियों को उदार ह्रदय होने की सलाह दी और इस प्रकार बिहार की जनता ने फिर से सत्ता के केन्द्रीकरण के खिलाफ अपना अपना जनादेश दिया. सामाजिक नया के साथ आर्थिक विकास का तालमेल एक मज़बूत विपक्ष के रूप में लोकतंत्र के खम्बे को मजबूती देगा.

2. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ राजनीतिक शक्ति लम्बे समय तक उच्च जाति एवं वर्ग के पास रही. लेकिन मध्यम वर्ग भी राजनीतिक- आर्थिक हिस्सेदारी के लिए लम्बे समय से अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगा रहा. यहाँ की पारंपरिक सत्ता को तथा राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व को चुनौती 1970 के दशक में मिलने शुरू हुई. और 1990 के दशक में पिछड़े वर्ग की राजनीति का उभर अपने चर्म पर था जब लालू यादव ने बिहार के मुख्य मंत्री के रूप में सत्ता संभाला. सत्ता का लोकतंत्रीकरण एक झटके में नहीं हुआ बल्कि इसके लिए एक लम्बा समय लगा जिसकी जड़े स्वतंत्र से पहले से देखी जा सकती हैं. कृषि योग्य भूमि पर मुख्य रूप से बिहार में तीन जातियों के पास एकाधिकार था – राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण . पिछड़े वर्ग के पास जैसे कोइरी, कुर्मी और यादव के पास ज़मीन का एक छोटा स हिस्सा था. जबकि निम्न वर्ग के पास कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाये तो अधिकांश लोग भूमिहीन खेतिहर मजदूर बने रहे. हालांकि स्वतंत्र से पहले स्वाधीनता आन्दोलन के समय से कुछ लोग भूमि सुधार की मांग को लेकर लड़ रहे थे. जैसे की स्वामी सहजानंद किसान सभा के बैनर तले किसान आन्दोलन को नेतृत्वा दे रहे थे. कहा जाता है की ये इस अन्दोअलं का सबसे ज्यादा फ़ायदा पिछड़ी जातियों को मिला और उच्च वर्ग को इसका घटा झेलना पड़ा. भूमि सुधर का अधिकतम फायदा पिछड़ी वर्ग की जातियों को मिला जो एक नए कृषक वर्ग के रूप में उभर कर आया जिसे कुलक कहा जाने लगा. आर्थिक उभार के साथ साथ इस वर्ग में राजनैतिक उभर की भी आकांक्षा जागी और इस वर्ग ने राजनैतिक तौर पर भी अपनी जगह बनानी शुरू की. 1980 के दशक के आन्दोलन से दबे कुचले पिछड़े समाज को सशक्तिकरण का भान हुआ हालाँकि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में कुछ खास सफलता हासिल करने में अक्षम रही. क्यूंकि शीघ्र ही पिछड़ा वर्ग खुद में टूटने और बिखरने लगा. पहले खेमे का नेतृत्व लालू यादव के जनता दल और दूसरा खेमा जिसमे कुर्मी और कोइरी शामिल थे समता पार्टी के रूप में संगठित हुए.

3.वामपंथी पार्टियों की भूमिका

मुख्यधारा की वामपंथी पार्टिया जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया मार्क्सिस्ट ने जनता दल के प्रमुख गठबंधन साथी की भूमिका निभाई. CPIML मात्र एक बार समता पार्टी का गठबंधन साथी रहा. हलाकि जनता दल ने अपना वर्चास्वा बनाये रखा लेकिन फिर भी एक लम्बे समय तक CPI और CPM इसके प्रमुख साथी रहे.[1]

लालू प्रसाद के चारा घोटाले के बावजूद जनता दल बिहार में सत्ता में बनी रही. क्यूंकि इन्होने सामाजिक नयाए के मुद्दे को जिन्दा रखा और गरीब पिछड़ों के हक़ की लड़ाई में डेट रहे. चाहे और जो

[1]संजय कुमार, न्यू फेज इन बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स इन बिहार: जनता दल ऑन डिक्लाइन, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, पेज. 2472-2473.

RRIJM 2015, All Rights Reserved

भी कमियां रही हो लालू के नेतृत्व वाले जनता दल ने धार्मिक उन्माद के खिलाफ धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में अपना मोर्चा खोले रखा.[2]

जहाँ तक वामपंथी पार्टियों की बात है तो उन्होंने समय - समय पर अपने पुनरीक्षण रिपोर्ट में इस बात को स्वीकर है कि उनका वर्ग आधारित जनाधार में सुस्ती आई है और उनकी पार्टी के आधार वर्गीय में गिरावट भी आई है. (राष्ट्रीय कार्यकारिणी CPIरिपोर्ट मार्च 1998). पार्टी का यह भी मानना है कि सामाजिक न्याय के नाम पर ए पार्टी के अन्दर के भटकाव को रोकने में भी वे अक्षम रहे. सक्षिप्त में यदि कहें तो CPI ने इस बात को स्वीकार कि जबसे उन्होंने लालू सरकार में गठबंधन धरम निभ्य तब से उनकी अपनी पार्टी का वर्गीय पहचान में गिरावट आई है. हलाकि जाति का सवाल कम्युनिस्ट पार्टी में लम्बे समय से रह किन्तु इसकी वजह को इन्होने कभी भी गंभीरता से पार्टी के भीतर नहीं रखा. इन्होने उत्तर माडल परिघटना को ठीक ढंग से नहीं समझा और अपपने बचे खुचे जनाधार को भी खोते गए. यहाँ दूसरी दलील ये भी दी जाती है कि पार्टी खुद अपने राजनैतिक पहचान और सिधान्तों से भी भटकती गई जीकी वजह से धरातल पर उनके वोट में भी काफी गिरावट आई. क्यूंकि न वो अपने वर्गीय चरित्र को बचा पाए और ना ही पिछड़े वर्ग के उभार को समझ पाए. वो धारा के साथ बहते गए.

कम्युनिस्ट पार्टी अपने जनाधार को पिछड़े वर्ग के उभर के बाद भी बचा सकती थी यदि वो अपने जनाधार के बीच आर्गेनिक संवाद बना कर रखती, कृषक और मजदूर वर्ग के लड़ाई में अपनी अहम् भूमिका में रहती, और धीरे धीरे जाति को भी समझकर उसका हल निकलते. हलाकि CPI ने चारा घोटाला के बाद अपने वर्गीय छवि और बचे खुच सैधांतिक मूल्यों को बचने के लिए जनता दल से अलग अपनी खुद की पहचान फिर से स्थापित करने की बात को अपने पार्टी डॉक्यूमेंट में इगित किया परन्तु इतना काफी नहीं था. कुछ बुद्धजीवियों का कहना था कि मुख्यधारा की वाम दल का जनता दल से केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही विचारधारा का टकराव कैसे हो सकता है? क्या और सारे लोकतंत्रिक मुद्दे पर उनकी जनता दल से सहमती है ? संक्षिप्त में कहें तो मुख्यधारा के वाम दलों को को कुछ बुनियादी बदलाव अपनी पार्टी के ढांचे में करने हे होंगे नहीं तो संभव है कि शेष जनाधार का भी ह्रास हो जाये.[3]

बिहार के वाम दलों ने 2009 के लोक सभा चुनाव में एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिसमे उन्होंने (CPI, CPM, CPI-ML) ने मिलकर यूनाइटेड लेफ्ट ब्लॉक बनाया. हलाकि राजनीतिक हलके में वाम दलों के संगठित रूप से चुनाव लड़ने की बात काफी समय से चल रही थी. क्यूंकि वाम दलों के वोटो का बंटवारा भी इनके ख़राब चुनावी प्रदर्शन का एक कारण माना जाता रहा है. जिसके कारन 1998 और 2004 के लोक सभा चुनाव में बिहार से एक भी वाम दल का उम्मीदवार चुनकर नहीं जा सका. ज़ाहिर है चुनाव के सभी वाम दलों के अपने अलग मैंने हैं. जैसे CPI और CPM चुनाव कवक कुछ सीटों पर लड़ते हैं जहाँ उनकी अच्छी पकड़ है , जीत की उम्मीद है या फिर वोट शेयर बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है जबकि CPI -ML (LIBERATION) हमेशा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार देती रही हैं क्यूंकि उनका मानना है कि चुनावी प्रचार में शामिल होने से वो अपना जनाधार बचा पाएंगे या फिर बढ़ने की भी उम्मीद रखते हैं. लिबरेशन चुनाव में जीत और हार की चिंता कम करता है और अपने वजूद और पहचान को बचाना ज्यादा आवश्यक मानता है.[4]

4.भूमि का सवाल

इसके अलावा तीनों वाम दलों के भूमि सुधार को लेकर अपनी लड़ाई भी अलग -अलग वर्ग पर जोर देते हैं. हलाकि की भूमि की लड़ाई में वाम दलों के आन्दोलन को देखकर BJP ने बिहार विधान सभा में लालू सरकार को इसके परिणाम की चेतावनी भी दी थी. ज़मीन बंटवारे के मामले में कांग्रेस पार्टी BJP के साथ कड़ी रही. पहली बार विधान सभा में फ्लोर का बंटवारा वर्ग के अधर पर हुआ. लालू ने इस बात के लिए वाम को यकीन दिल्या की वो अपनी पुलिस को आन्दोलनरत कृषकों पर गोली नहीं चलने देगी.

एक बार फिर से वाम दलों के बीच अपने वर्ग चरित्र को लेकर फूट हुआ जब लिबरेशन ने ज़मीन के राष्ट्रियकरण की बात की. ज़मीन का राष्ट्रीयकरण CPI और CPM के एजेंडा में नहीं था. इनकी पार्टी लाइन के मुताबिक जो बनी बनाई नीति ज़मीं को लेकर पहले से ही अस्तित्व में है उसको लागू किया जाये. इस प्रकार वाम दलों के अपने सांगठनिक चरित्र में भिन्नता भी इनकी यूनिटी में आड़े आई. वाम दलों ने बिहार की मुख्यधारा की क्षेत्रीय दलों (JDU, RJD, LJP) के चरित्र का आंकलन भी अलग- अलग इस आधार पर किया किया कि भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों से इस क्षेत्रीय पार्टियों के कैसे संबंध रहे हैं.[5]

जब लालू यादव ने यादव जनता दल के बैनर तले यादव और मुस्लिम का फार्मूला बनाकर सोशल इंजीनिरिंग किया तब वामदलों का अपना आत्मनिर्भर राजनीतिक दावेदारी और मुश्किल गई. उदाहरण के तौर पर सीपीआई पटना पार्लियामेंट्री सीट से मध्यावधि चुनाव में सारी वाम दलों के सहयोग के बावजूद बुरा प्रदर्शन करती है. इसके बावजूद सीपीआई ने अपना आंतरिक मुल्यांकन करना ठीक नहीं समझा. बल्कि राष्ट्रीय पार्टियों पर आरोप लगाया की भाजपा और कांग्रेस जैसी सत्ताधारी पार्टियों द्वारा इलेक्शन के दौरान धांधली की गई. जहाँ तक धांधली की बात है तो बिहार के चुनावी राजनीति में उतनी पुरानी है जितनी की बिहार इलेक्शन की शुरुआत . यह दर्शता है की जनता से से प्रत्यक्ष जुडाव का आभाव पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी रही . और उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात ये रही की मुख्यधारा की लेफ्ट पार्टी अपना अलग पहचान और अस्तित्व खो कर क्षेत्रीय पार्टियों/ सत्ताधारी की पिछलग्गू बन गई .[6] इस बात को सीपीआई ने अपने 14 वे पार्टी कांग्रेस के रिपोर्ट में भी इंगित किया की कमजोर इलाकों में कुछ

[2]वही, p.2475.

[3]देखें www.Kafila.org आदित्य निगम द्वारा लिखित, ' द डिक्लाइन ऑफ़ कम्युनिस्ट मास बेस इन बिहार: जगन्नाथ सरकार', सितम्बर, २०११

[4]चिराश्री दासगुप्ता, ' द यूनाइटेड लेफ्ट ब्लॉक् इन बिहार', इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम नंबर-४४,पेज-१०-१५, २००९.

[5]वही 16

[6]तिलक डी गुप्ता, 'प्रोब्लेम्स ऑफ़ लेफ्ट असर्सन इन बिहार: पटना पोल लेसन्स', इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम नंबर-२८,पेज-१२७९-८०-१५, १९९३.

सीटें पा लेने की चिंता में उन्होंने अपने बचे खुचे आधार को भी क्षेत्रीय पार्टियों को सौंप दिया.

5. निष्कर्ष :

वर्तमान में 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनावी समीकरण में कुछ उदारता और व्यापकता का दौर चला जिसमें पार्टियों ने अपने तालमेल और सामंजस्य आपसी नफे नुक्सान से से ऊपर उठकर देश के बड़े मुदद जैसे शिक्षा , रोज़गार, प्रवासी मजदूर, मान -सम्मान, और सबसे महत्वपूर्ण बात सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय पर जोर दिया गया. वाम दलों ने 16 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अपनी प्रासंगिगता को स्थापित किया.

सन्दर्भ सूची

[1]. संजय कुमार, न्यू फेज इन बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स इन बिहार: जनता दल ऑन डिक्लाइन, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, पेज. 2472-2473.

[2]. देखें www.Kafila.org आदित्य निगम द्वारा लिखित, ' द डिक्लाइन ऑफ़ कम्युनिस्ट मास बेस इन बिहार: जगन्नाथ सरकार', सितम्बर, २०११.

[3]. चिराश्री दासगुप्ता, ' द यूनाइटेड लेफ्ट ब्लॉक् इन बिहार',इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम नंबर-४४,पेज-१०-१५, २००९.

[4]. तिलक डी गुप्ता, 'प्रोब्लेम्स ऑफ़ लेफ्ट असर्सन इन बिहार: पटना पोल लेसन्स', इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम नंबर-२८,पेज-१२७९-८०-१५, १९९३.

RRIJM 2015, All Rights Reserved